SHRI B. K. DASCHOWDHARY : It is in West Bengal.

SHRI K. R. GANESH : Actually, parts (b) and (c) of the main question relate to the Ministry of Food and Agriculture who are dealing with this. Since part (a) relates to my Ministry, the question has come to us. But as regards the working of this scheme, the question should be addressed to the Ministry of Food and Agriculture.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY : Let him kindly refer the matter to the concerned authorities.

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, 1969-70 में हमने अपने देश से 33 करोड़ रुपये का तम्बाकू विदेशों को निर्यात किया था । इसका मतलब यह है कि तम्बाकू के उत्पादन से काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है, यदि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, इस में निर्धन तम्बाकू उत्पादकों को कुछ विशेष सहायता दिये जाने की बात है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में आप कोई राष्ट्रीय पालिसी निर्धारित करना चाहते हैं ताकि वह चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, जहां भी तम्बाकू का उत्पादन होता है, वहां के किसानों को कुछ सहायता मिल सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कूच-बिहार के थोड़े से एरिये का है, आप इस को कहां से कहां ले गये । इसका फाइनेन्स डिपार्टमैन्ट जवाब नहीं देगा, आप इस सवाल को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को एड्रेस करें ।

श्री रामचन्द्र विकल : तम्बाकू पर किसानों से जो उत्पादन शुल्क लिया जाता है वह वजन के आधार पर होता है, जिसमें काफ़ी भ्रष्टाचार होता है । क्या आप इसको बीघों के आधार पर लेने का विचार रखते हैं ?

SHRI K. R. GANESH : No, there is no proposal. It is after a great deal of consideration that the present policy has been evolved.

पटना में गंगा नदी के ऊपर पुल का निर्माण

1180. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना में गंगा नदी पर पुल के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस पुल का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है और इस पर कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग): सभा पटल पर एक विवरण पत्र रखा गया है ।

विवरण

(क) से (ग). पटना के निकट गंगा नदी के ऊपर का प्रस्तावित पुल एक स्थानीय सड़क पर पड़ता है । अतः इस की योजना, निविदाओं को आमंत्रित करने, निर्माणकार्य का ठेका देने कार्यनिष्पादन, इत्यादि, से संबंधित सभी मामलों से मुख्यतः बिहार सरकार सम्बन्धित है । उसके द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार अब तक इस परियोजना में निम्नलिखित प्रगति हुई है :-

(1) पुल के लिए निविदाएं प्राप्त हो गयी हैं और राज्य सरकार उनकी संवीक्षा कर रही ।

(2) स्थायी भूमि का अर्जन और स्थानीय कार्यालयों और गोदामों का निर्माण कार्य राज्य सरकार ने प्रारम्भ कर दिया है और वह जारी है ।

राज्य सरकार के इस पुल को 1978 तक पूरा करने की संभावना है । इस पर 23.50 करोड़ रु० लागत आने का अनुमान है और बताया गया है कि जून 1971 तक राज्य सरकार ने कुल 7613-974 रु० इस पर व्यय किये हैं ।

श्री शंकर दयाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, गंगा पर कानपुर में पुल है, इलाहाबाद मे पुल है, बनारस में पुल है, जहां तक मैं समझता हूं पटना ही एक ऐसा अभागा शहर है, जहा गंगा पर पुल नहीं है...

अध्यक्ष महोदय : आप ने वह पत्र पढ़ा है या नही ?

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। यह गंगा पर जो प्रस्तावित पुल है, इस का शिलान्यास 1970 में प्रधान मत्री जी ने किया था और उस समय उन्होंने कहा था कि इसमें पैसे की कमी नही आयेगी। लेकिन क्या यह सच है कि पैसे के अभाव में इस पुल का काम रुका पड़ा है। जिन्होंने टैण्डर दिये थे, उनमे से कोई भी शुरू करने नही जा रहे है। उन लोगों का कहना है कि जब पूरा पैसा इसके लिये नही जुटेगा, तब तक काम की शुरुआत नही होगी।

श्री राज बहादुर : श्रीमन्, जहां तक दुर्भाग्य या सौभाग्य का प्रश्न है, यह सौभाग्य का विषय है कि पटना मे यह पुल बनेगा। जहां तक इस का सम्बन्ध है, यह राष्ट्रीय मार्ग पर नही आता है, बल्कि राज्य मार्ग पर आता है, प्रदेश के मार्ग पर आता है ...।

श्री रामावतार शास्त्री : इसको राष्ट्रीय मार्ग बना लीजिये।

श्री राजबहादुर : जहां तक राष्ट्रीय मार्ग बनाने की बात है, उसके लिये पर्याप्त धन-राशि का प्रबन्ध किया जाय, वह मेरे और आप के हाथ में नही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तब तक नदी कैसे पार होगी।

श्री राज बहादुर : यह निश्चित बात है कि पुल का जो प्रस्ताव था, वह मन्जूर हो चुका है और गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने यह स्वीकार किया है कि 50 परसेन्ट या उस की एक सीमा दी गई है, जैसा कि पत्रावली में लिखा गया है, 4.5 करोड़ रुपया या इस हद तक जो इसमें थोड़ा हो, वह हम देंगे। इसके बारे में टेण्डर्स मंगा लिये गये हैं, एक्वीजीशन की कार्यवाही भी हुई है और दूसरी कार्यवाहियां भी हो रही हैं और मैं समझता हूं कि इस पुल के निर्माण की ओर हम आशा की दृष्टि से देख सकते है।

श्री शंकर दयाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पुल पर पूरा खर्च शायद 23 करोड़ 50 लाख होने वाला है, लेकिन केन्द्र सरकार ने अब तक इस के लिए केवल 4.50 करोड़ की राशि दी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस 4.50 करोड़ के बाद आप कितनी और धनराशि इस के लिए देने जा रहे है ?

श्री राज बहादुर : अभी तो सिर्फ साढे चार करोड ही मन्जूर हुए है।

श्री शंकर दयाल सिंह : इस मे कैसे बनेगा। जिन्होने टेण्डर दिये है उन का कहना है कि जब तक पूरा पैसा नही आयेगा, हम काम शुरू नही करेंगे। साढे चार करोड रुपये से कैसे पुल बनेगा, यह बतलाइये ?

श्री राज बहादुर : यह मेरी जानकारी में नही है कि जिन्होने टेण्डर दिये है उन्होने बनाने से इन्कार कर दिया है। जिन्होंने टेण्डर दिये है उन में तीन बड़ी विख्यात कम्पनियां है, जो पुल बनाती है और मैं आशा करता हूं कि वे अपना काम शुरू कर देगी।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या यह बात सच है कि पटना पुल के निर्माण के सिलसिले में सैकड़ो घरो के निवासी विस्थापित किये जाने वाले हैं ? यदि हां तो क्या सरकार ने उन के पुनर्वास की कोई योजना बनाई हैं ? अगर बनाई है और उस योजना के बारे में आप को कोई जानकारी है तो बतलाइए।

श्री राज बहादुर : श्रीमन्, यह स्पष्ट है कि जब पुल बनेगा तो शायद कुछ लोगों की जमीन ली जाय, कुछ घर लिए जायं और जो कायदा है, जो नियम है राज्य सरकार का ऐक्वीजीशन के बारे में उस के अनुसार जो भी मुआवजा है वह दिया जायगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA From the statement laid on the Table of the House it appears that the Government of India is almost like a spectator looking on so far as this project is concerned, although it has been said that they have promised assistance to the excent of Rs 4 5 crores May I know what exactly is going to be their contribution in terms of expertise and also in terms of financial assistance so far as the whole project is concerned ?

SHRI RAJ BAHADUR We have extended our co operation As I said earlier, the project lies on a State road, and essentially the responsibility for its planning, designing, construction, etc , rests on the State Government We have come in a special way to assist the State Government because of the importance of the project.

SHRI KARTIK ORAON Construction or no construction we would like to know from the Government the guidelines which were taken into consideration while accepting this site for construction of the bridge

SHRI RAJ BAHADUR I think the hon Member knows that Messrs J J White Engineering Corporation of the United States came and advised the State Government in regard to the location of the bridge They recommended a particular site which was, however, protested against by some local representatives and MLAs Then there was a committee formed consisting of the Chief Engineer, Public Works Department, Secretary, Public Works Department, the Development Commissioner etc On their advice the location has been shifted, and that is exactly the position at present

श्री यमुना प्रसाद मंडल : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि यह स्थानीय सडक पर है। लेकिन सब लोग जानते है इस बात को कि राष्ट्रीय मार्ग न० 28 और 30 से इसका सम्बन्ध है और सारे बिहार-निवासियो को योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार की ओर से यह आश्वासन मिला है कि पुल के बनाने मे किसी तरह की देरी नही होगी। ऐसी हालत मे जैसा 'विवरण' से मालूम होता है कि 1978 तक योजना चलेगी तो 74 के बाद पचम पच वर्षीय योजना मे यदि आप आश्वासन नही देते तो फिर यह ग्लोबल टेडर देने वाली विख्यात फर्म कैसे काम आगे बढा सकेगी ?

श्री राज बहादुर मुझे पूरी सहानुभूति है इस प्रोजेक्ट के साथ और इस पुल के निर्माण के साथ। लेकिन मैंने जैसा कहा कि केन्द्रीय सरकार का दायित्व इस मे सीमित है और जितनी भी सहायता दी जा सकती है वह देने का वचन दिया गया है।

ग्लोबल टेडर जरूर दिया था लेकिन उस के परिणाम-स्वरूप केवल तीन कम्पनियो ने ही टेंडर दिये है, अन्य किसी ने नही दिए है, किसी बाहर की कम्पनी ने नही दिए है। मैं ऐसा विश्वास करता हू, उन्होने और बडे पुल बनाए है, राष्ट्रीय मार्ग न० 28 पर मैं समझता हूँ कि मोकामे का पुल पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार के खर्चे पर बना है।

Excise Duty on Skimmed Milk Powder

*1183 SHRI INDER J MALHOTRA Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) the rates of excise and other duties on the production and marketing of skimmed milk powder in the country ,

(b) whether the cost of production of skimmed milk powder is higher as compared to landed cost of imported powder , and

(c) if so, the steps proposed to be taken with a view to strengthening economy of skimmed milk plants, encouraging indigenous production and offering incentives and removing disincentives ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K R GANESH) (a) The rate of Excise duty leviable on skimmed milk powder is 10% *ad valorem* The information about Sales-tax, if any, levied by the different States is being collected and when received will be laid on the Table of the House

(b) Yes, Sir.